[श्री खारबेल स्वाइं]

मैं उनसे वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील करूंगा ताकि हम उन्हें यह दिखा सकें कि उदयपुर, तालासरी और चांदीपुर बेहतरीन समुद्री तट हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 5.01 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

बावनवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती सुषमा स्वराज से कार्य मंत्रणा समिति का बावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। उसके पश्चात्, प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याा मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अब, माननीय प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 5.02 बजे

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री की जर्मनी, सेंट पीटर्सबर्ग, एवियान और चीन की हाल की यात्रा

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, पिछले दो महीनों में मुझे जर्मनी, रूस, फ्रांस और चीन की अपनी यात्रा के दौरान विश्व के कई नेताओं से मिलने का अवसर मिला।

मैंने दिनांक 27 से 30 मई तक जर्मनी की यात्रा की। उसके बाद, मैं राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर सेंट पीटर्सबर्ग के त्रिशताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए वहां गया। तत्पश्चात् मैं राष्ट्रपति शिराक के निमंत्रण पर एवियान में जी-8 की विस्तृत वार्ता में शामिल हुआ। दिनांक 22 जून से 27 जून तक मैंने अलग से चीन की यात्रा की।

जर्मनी और चीन की मेरी यात्राएं द्विपक्षीय थीं जबकि रूस और फ्रांस की यात्रा महत्वपूर्ण घटनाओं के उपलक्ष्य में थीं जिनमें केवल चुनिंदा देशों को ही आमंत्रित किया गया था। ये सभी यात्राएं यूरोप और एशिया के प्रमुख देशों के साथ हमारी चलती हुई बातचीत तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के बढ़ते हुए महत्व की मान्यता को दर्शाती हैं। मेरी इन यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का मौका मिला। ऐसी यात्राओं से हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर दूसरे देशों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है।

जर्मनी की मेरी यात्रा चांसलर श्रोएडर के निमंत्रण पर थी जो उन्होंने अक्तूबर 2001 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान मुझे दिया था। जर्मन नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने और उनमें तेजी लाने के बारे में मेरी उपयोगी बातचीत हुई। हमने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का विस्तार से आदान-प्रदान किया। जर्मनी का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए चाहे वह कहीं भी हो और किसी के भी विरुद्ध चलाया गया हो।

भारत और जर्मनी, दोनों ही व्यापार और निवेश संबंधों में और तेजी लाने के इच्छुक हैं। मैंने भारत में निवेश के अवसरों तथा भारत और जर्मनी के बीच अनेक अनुपूरक पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को अधिक बढ़ावा मिलता है। मुझे अनेक जर्मन सांसदों, व्यापार प्रतिनिधियों तथा भारत-विद्याशास्त्रियों से मिलने का मौका भी मिला। म्यूनिख में मेरी बवेरिया के मंत्री-अध्यक्ष एडमंड स्टोइबर के साथ लाभप्रद बातचीत हुई।

जर्मनी जो यूरोपी संघ में हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्ताकारों में से एक है तथा जो जी-8 देशों का सदस्य और इस समय सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है, के साथ अपने लगातार बढ़ रहे उच्च-स्तरीय संबंधों को हम महत्व देते हैं। प्रति वर्ष शिखर बैठकें आयोजित करने के हमारे निर्णय के अनुरूप हम अगले वर्ष चांसलर श्रोएडर के भारत आगमन की प्रतीक्षा में हैं।

सेंट पीटर्सबर्ग का 300वां वर्षगांठ समारोह शानदार एवं प्रभावशाली ढंग से मनाया गया। इस विशेष समारोह के लिए भारत को आमंत्रित करना भारत तथा रूसी संघ के बीच घनिष्ठ स्ट्रेटेजिक संबंधों का द्योतक है। यह भी कहना उचित होगा कि इस समारोह में विश्व के प्रमुख नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी रूस के महत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान की प्रतीक थी।

सेंट पीटर्सबर्ग की मेरी यात्रा के दौरान मुझे राष्ट्रपति पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक, चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का अवसर मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बुश से भी मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई।

राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। हम, दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और गहरा बनाने की रूस की प्रतिबद्धता को दोहराया। वार्षित शिखर सम्मेलन की हमारी सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप, मुझे आशा है कि मैं रूस का निकट भविष्य में द्विपक्षीय दौरा करूंगा।

जी-8 देशों के साथ व्यापक बातचीत के लिए कुछ चुने हुए विकासशील देशों को आमंत्रित करने की पहल के लिए मैंने राष्ट्रपति शिराक को धन्यवाद दिया। बहुध्रुवीय विश्व के महत्व पर हमारी समान समझ थी जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन करना जरूरी माना गया।

प्रधान मंत्री ब्लेयर के साथ हुई बातचीत में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर संतोष व्यक्त किया। प्रधन मंत्री ब्लेयर ने हमारी महत्वपूर्ण चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और समझ-बूझ दर्शाई।

चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ मेरी मुलाकात में, उन्होंने कहा कि चीन का नया नेतृत्व भारत के साथ मित्रता बढ़ाने पर बल देता है। हम इस बात पर सहमत हुए कि चीन और भारत, जो विश्व की कुल आबादी का एक-तिहाई भाग है, को मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए ताकि 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाया जा सके।

भारत उन 14 विकासशील देशों में से एक था जिन्हें एवियान में जी-8 देशों की विस्तृत वार्ता में आमंत्रित किया गया। इस वार्ता में स्वतंत्र रूप से तथा खुलकर बातचीत हुई जिसमें विभिन्न आर्थिक, विकास, पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी तथा अन्य मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं पर प्रकाश डालने का मौका मिला।

मैंने अपने भाषण में, सहस्त्राब्दि विकास दौर के निष्कर्षों पर सार्थक अनुवर्ती कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया जिससे एक ऐसी विश्व-व्यापार व्यवस्था बनाई जा सके जो विकास को बढ़ावा दे सके। मैंने मौजूदा प्रतिबद्धताओं का पालन करने तथा विशेषकर अल्प विकसित देशों में विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन पैदा करने के नए विचारों की जांच करने की जरूरत पर बल दिया। मैंने सुझाव दिया कि यद्यपि क्योटो प्रोटोकोल की पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी, जैसा कि प्रोटोकोल में व्यवस्था की गई है, प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के जरिए स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकासशील देशों को उनके जैव-विविधता संसाधनों तथा उनके परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए समुचित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। मैंने इस कटु सत्य की ओर ध्यान दिलाया कि यदि इन क्षेत्रों में तत्काल और स्पष्ट प्रगति नहीं होती तो विकासशील देशों में आर्थिक उदारीकरण तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यावरण उपायों के लिए राजनैतिक समर्थन जल्दी ही विखंडित हो जाएगा।

जी-8 शिखर बैठक के अवसर पर मुझे ब्राजील तथा मैक्सिको के राष्ट्रपतियों से मिलने का अवसर मिला। दोनों ही राष्ट्रपति इस बात पर सहमत थे कि विकासशील देशों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मुद्दों पर एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन बनाने, जी-15 जैसे समूहों में प्रभावी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

जी-8 देशों की विस्तृत वार्ता विकसित और विकासशील देशों के बीच उच्चतम स्तर पर संपर्क बनाने का एक उपयोगी मंच बन सकती है। एवियान में पधारे कई प्रतिभागियों ने यह विचार प्रकट किया कि भविष्य में जी-8 की अध्यक्षता करने वाले देश इस पहल को जारी रखें।

मैंने प्रधान मंत्री वन ज्याबाओ के निमंत्रण पर इस वर्ष 22 से 27 जून तक चीन की यात्रा की। लगभग दस वर्ष के बाद भारत के प्रधान मंत्री की यह चीन की पहली यात्रा थी। इस यात्रा से मुझे चीन के नए नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। चीन में मेरा बड़ी गर्मजोशी और शालीनता के साथ स्वागत किया गया तथा मुझे इस बात का विशिष्ट रूप से एहसास दिलाया गया कि वे भी हमारी तरह परस्पर सद्भाव बनाने तथा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में विविधता लाने के लिए पूरी तरह इच्छुक

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हैं। मेरी सभी बैठकों के दौरान आपसी विश्वास और समझ-बूझ पैदा करने की चल रही प्रक्रिया को मजबूत करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

हमने दस समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनकी सूची सदन के पटल पर रखी गई है। भारत-चीन संबंधों में पहली बार दो प्रधान मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त घोषणा-पत्र संलग्न है तथा सदन के पटल पर रखा गया है। इस घोषणा-पत्र में उन सिद्धांतों और समान विचारों का उल्लेख किया गया है जिनसे हमारे द्विपक्षीय संबंधों के भावी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें बहुध्रुवता की ओर बढ़ते हुए रुख को मजबूत करने के लिए, विश्व व्यापार संगठन संबंधी मुद्दों पर और विकासशील देशों की चिंताओं पर हमारे दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई है।

यह घोषणा-पत्र भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान को दोनों देशों द्वारा दिए गए महत्व को परिलक्षित करता है। इस प्रश्न के अंतिम हल के सिद्धांतों पर कुछ समय से विचार-विमर्श चल रहा है। प्रधान मंत्री वन ज्याबाओ और मैं इस बात पर सहमत हुए कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा समाधान के ढांचे की खोज के जारए इन चर्चाओं को एक नई गति प्रदान की जानी चाहिए। हमने इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे विशेष प्रतिनिधि होंगे। चीन ने अपनी ओर से अपने सबसे वरिष्ठ उप विदेश मंत्री को नियुक्त किया है। प्रधान मंत्री वन ज्याबाओ तथा मैं इस बात पर भी सहमत हुए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण से संबंधित संयुक्त कार्य सहज रूप से जारी रहे तथा सीमा क्षेत्रों में बनी शांति और अमन-चैन को बरकरार रखा जाए।

हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर विशेष बल दिया गया। मेरी यात्रा के दौरान चीन में सी.आई.आई., फिक्की तथा एसोचम के वरिष्ठ व्यवसायियों का एक बड़ा शिष्टमंडल मौजूद था। मैंने बीजिंग तथा शंघाई में भारत और चीन के व्यवसायियों की दो बैठकों को संबोधित किया जिनमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री बीजिंग में चीन के संबद्ध मंत्रियों से मिले। उन्होंने संबंधित एजेंसियों तथा चीन के व्यावसायियों के साथ भी गहन विचार-विमर्श किया। हमारे संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिवेश मंत्री ने भी इसी तरह शंघाई में उपयोगी बातचीत की।

दोनों ही पक्ष हमारे आर्थिक संबंधों की क्षमता से भली-भांति अवगत थे। यह द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में संभावित प्रतिपूरक पहलुओं का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल गठित करने के निर्णय में परिलक्षित हुई। यह संयुक्त अध्ययन दल दोनों देशों की सरकारों को व्यापार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने तथा हमारे व्यापार समुदायों के बीच अधिक से अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करेगा। हमने आर्थिक संवाद एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया जिससे इस क्षेत्र में हमारा समन्वय मजबूत हो।

एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत-चीन सीमा पर नाथूला दर्रे से सीमा व्यापार संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए एक तीसरा सीमा दर्रा नियुक्त हो गया है। इस ज्ञापन के साथ ही हमने एक ऐसी प्रक्रिया की भी शुरूआत कर दी है जिससे भविष्य में भारत-चीन संबंधों में सिक्किम एक मुद्दा नहीं रहेगा।

तिब्बत के संबंध में, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी दशकों पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमने कभी भी इस पर संदेह व्यक्त नहीं किया कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र चीन लोक गणराज्य की भूमि का हिस्सा है। इसलिए, इसे दोहराने के विरुद्ध कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। हमने श्रद्धेय दलाईलामा अथवा तिब्बती शरणार्थियों की भारत में उपस्थिति के बारे में कोई नई बात नहीं कही है।

मेरी यात्रा के दौरान हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी नए सिरे से बढ़ावा मिला। हम दिल्ली और बीजिंग में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मैंने बीजिंग विश्वविद्यालय में एक भारतीय अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन किया तथा इस केन्द्र को चलाने के लिए भारत की ओर से कुछ अंशदान देने की घोषणा की। हमने अगले वर्ष पंचशील, जो कि भारत-चीन संबंधों की एक आधारशिला है, की 50वीं वर्षगांठ मनाने पर सहमति व्यक्त की है। मुझे लोयांग में व्हाइट हार्स टैंपल जाने का सुअवसर मिला जो भारत से चीन आने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षुओं के आगमन का प्रतीक है तथा जो हमारे संबंधों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयाम को रेखांकित करता है। चीनी पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु अतिरिक्त मार्ग खोलने के मेरे सुझाव पर विचार करने पर भी सहमत हुआ है।

मेरी इस यात्रा के दो उद्देश्य पूरे हो गए—चीन के नए नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, और हमारे विविध द्विपक्षीय सहयोग को नई गति प्रदान करना। हम चीन से इस बात पर सहमत

हैं कि हम सौहार्दपूर्ण चर्चाओं के जरिए अपने मतभेदों को दूर करने के प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक संबंध बनाए रखेंगे।

मैं इन सभी यात्राओं के नतीजों से संतुष्ट हूं। जर्मनी के साथ हमारी वार्ता सुदृढ़ हुई है। राष्ट्रपति पुतिन एक बड़े बहुपक्षीय कार्यक्रम के मेजबान के रूप में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद, पहले ही दिन आधी रात के बाद मेरे साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए आए। यह इस बात का सूचक है कि वे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देते हैं। राष्ट्रपति शिराक ने जी-8 विस्तृत वार्ता का इस ढंग से संचालन किया जिससे विकासशील देश होने के नाते हमारे विचारों का मूल महत्व उजागर हुआ। चीन के साथ आपसी विश्वास और समझबूझ बढ़ाने की दिशा में प्रगति हुई है।

जिन नेताओं से भी मैं मिला, सभी ने स्वाभाविक रूप से दक्षिण एशिया की स्थिति में रुचि दिखाई। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि हमने पाकिस्तान की ओर मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है, उसका सभी नेताओं ने समर्थन किया और सराहना की तथा यह आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान भी इसका प्रत्युत्तर देगा। सभी ने आतंकवाद के खतरे की कड़े शब्दों में निंदा की। मैं यह समझता हूं कि मेरे वार्ताकार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने की हमारी नीति को पूरी तरह से समझते हैं।

अनुबंध

प्रधान मंत्री की चीन लोक गणराज्य की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतों की सूची

(1) भारत गणराज्य की सरकार के कानून तथा न्याय मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के सुप्रीम लोक अभियोजन सेवा के बीच सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

(2) भारत गणराज्य की सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा चीन लोक गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के बीच शैक्षिक सहयोग एवं आदान-प्रदान पर कार्यकारी कार्यक्रम।

(3) भारत से चीन को आमों के निर्यात हेतु फाइटोसेनेटरी जरूरतों के संबंध में भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय तथा चीन लोक गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा संगरोधन के सामान्य प्रशासन के बीच नयाचार।

(4) वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता-ज्ञापन।

(5) अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य की सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।

(6) भारत सरकार के महासागर विकास विभाग और चीन लोक गणराज्य के राज्य महासागरीय प्रशासन के बीच महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

(7) भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और चीन के राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच समझौता-ज्ञापन।

(8) भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार की बीच एक-दूसरे की राजधानियों में अपने सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी समझौता-ज्ञापन।

(9) भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच वर्ष 2003-2005 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधी कार्यकारी कार्यक्रम।

(10) भारत गणराज्य की सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच सीमा व्यापार बढ़ाने संबंधी समझौता-ज्ञापन।

भारत गणराज्य और चीन लोक गणराज्य के बीच संबंधों के सिद्धांतों एवं व्यापक सहयोग से सम्बद्ध घोषणा

चीन लोक गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधान मंत्री महामहिम वेन जियाबाओ के आमंत्रण पर भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री महामहिम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिनांक 22 से 27 जून, 2003 तक चीन लोक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान चीन के प्रधान मंत्री जियाबाओ ने प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी से वार्ता की। प्रधान मंत्री वाजपेयी के साथ वहां चीन लोक गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति हु जिंताओं, केन्द्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष जियांग जेमिन, नेशनल पिपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के चेयरमैन वु वांगुओ तथा चीन लोक गणराज्य के उपराष्ट्रपति जेंग जिंयागहांग से अलग-अलग वार्ता हुई ये वार्ताएं एवं बैठकें बहुत सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुईं।